फरार आरोपितों की अब खुलेगी पूरी आर्थिक कुंडली

बैंक खातेसे लेकर जमीन, मकान, वाहन और शेयर तक तलाशेगी पुलिस; पीएचक्यूने सभी एसपीको दिए निर्देश

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे आरोपितों के लिए अब सिर्फ गिरफ्तारी का दबाव नहीं होगा, बल्कि उनकी पूरी आर्थिक कुंडली खंगाली जाएगी। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी फरार रहने वाले आरोपितों की संपत्ति का ब्योरा पुलिस अलग-अलग सरकारी विभागों और एजेंसियों से जुटाएगी। इसमें बैंक खाते, जमीन-मकान, वाहन ही नहीं, शेयर, बांड और अन्य वित्तीय संपत्तियां भी शामिल होंगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। जिलेवार ऐसे फरार आरोपितों की सूची तैयार करने के साथ उनकी चल-अचल संपत्ति का चिञ तैयार कराया जा रहा है, ताकि जरूरत पडऩे पर यह जानकारी न्यायालय के सामने प्रस्तुत की जा सके।

पीएचक्यू के निर्देशों के मुताबिक किसी आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता और न्यायालय द्वारा तय तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय के आदेश के आधार पर उसकी संपत्ति कुर्क कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य फरार आरोपितों पर ऐसा दबाव बनाना है कि वे लंबे समय तक कानून की पकड़ से बाहर न रह सकें। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि संपत्ति कुर्क होने की कार्रवाई के डर से कई आरोपित न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं।

बैंक खाते से शुरू होगी आर्थिक पड़ताल

फरार आरोपित की आर्थिक स्थिति पता करने के लिए पुलिस अब बैंकिंग रिकॉर्ड भी खंगालेगी। बैंक खातों में जमा राशि और अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके साथ ही आयकर विभाग से आरोपित के आयकर रिटर्न की जानकारी ली जाएगी। पैन कार्ड और अन्य उपलब्ध विवरण के आधार पर उसके नाम पर मौजूद शेयर, ऋण पत्र, बांड और दूसरी वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने की कोशिश होगी। यानी आरोपी जिस संपत्ति को पुलिस की नजर से दूर समझकर बैठा है, उसका रिकॉर्ड दूसरे सरकारी सिस्टम से निकाला जा सकेगा।

जमीन-मकान का रिकॉर्ड राजस्व विभाग से

आरोपित के नाम पर जमीन, मकान या दूसरी अचल संपत्ति है तो उसका ब्योरा राजस्व विभाग से लिया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव, नगरीय निकाय और उप पंजीयक कार्यालय के रिकॉर्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि आरोपित का निवास कहां है और उसके नाम पर किस-किस स्थान पर संपत्ति दर्ज है। इससे किसी जिले में रहने वाले आरोपित की दूसरे जिले या क्षेत्र में मौजूद संपत्ति की जानकारी भी सामने आ सकेगी।

गाड़ी भी नहीं बचेगी

आरोपित के नाम पर कितने वाहन पंजीकृत हैं, इसकी जानकारी परिवहन विभाग से ली जाएगी। वाहन की जानकारी मिलने के बाद न्यायालय के आदेश के अनुसार उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें कार, दोपहिया या अन्य पंजीकृत वाहन भी जांच के दायरे में आएंगे।

केंद्रीय एजेंसियों से भी लिया जाएगा सहयोग

पुलिस मुख्यालय ने संपत्ति की पहचान के लिए केवल राज्य के विभागों तक व्यवस्था सीमित नहीं रखी है। जरूरत के अनुसार केंद्र की एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा। राजस्व विभाग से जमीन-मकान, नगरीय निकाय और उप पंजीयक कार्यालय से संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड, बैंकों से खातों की जानकारी, आयकर विभाग से वित्तीय विवरण और परिवहन विभाग से वाहनों का ब्योरा जुटाया जाएगा।

न्यायालय में रखा जाएगा संपत्ति का पूरा ब्योरा

पुलिस जिलेवार फरार आरोपितों की संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगी। इसके बाद न्यायालय के आदेश के आधार पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी अब फरार आरोपित को पकडऩे की रणनीति केवल उसके संभावित ठिकानों की तलाश तक सीमित नहीं रहेगी। उसके पैसों, जमीन और संपत्ति के रास्ते तक पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी।

प्रतिमा उठाते समय १ लाख का आईफोन चोरी

जबलपुर, (ईएमएस)। लार्डगंज थाना क्षेत्र में चोरी की दो वारदाते सामने आई हैं लार्डगंज गढ़ा फाटक के आगे लोहिया पुल के पास बरेला जा रही माता की प्रतिमा को उठाते समय एक युवक का आईफोन मोबाइल अज्ञात चोर चोरी कर ले गया वहीं रानीताल स्टील ब्रिज के पास केबल वायर काटकर अज्ञात चोर जंक्शन वाक्स, ड्राइवर, एमसीबी, बॉल बाशर लाईचट, कोर केविल व अन्य सामान चोरी कर ले गया। लार्डगंज पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिद्धनगर मानेगांव रांझी निवासी सिद्धनगर मानेगांव रांझी निवासी २२ वर्षीय बीटेक छात्र आयुष मेहरा गत रात लगभग ११ बजे गढ़ा फाटक के आगे लोहिया पुल के पास बरेला जा रही दुर्गा माता का वीडियो शूट कर रहा था, उसी समय माताजी की प्रतिमा को अन्य लोगों के साथ उठवाने लगा, तभी उसका मोबाइल आई फोन अज्ञात चोर चोरी कर ले गया चोरी गए फोन की कीमत लगभग १ लाख १२ हजार रूपये बताई गई है। इसी प्रकार प्रेमनगर मदनमहल निवासी एनसीसी कंपनी में उपप्रबंधक ३७ वर्षीय नीलापू आनंदा राव गत सुबह ६ से ७ बजे के बीच रानीताल स्टील ब्रिज के निरीक्षण हेतु अपने स्टाफ के साथ गया था ब्रिज के पास केबल वायर कटा था, चैक करने पर जंक्शन बाक्स, ड्राइवर, एमसीबी, बॉल बाशर लाईचट, कोर केविल व अन्य सामान अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है।

पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा ३०३(२) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पोर्टल की खामी में अटकी ३० हजार छात्रों की छात्रवृत्ति

१८० कॉलेजों के एससी विद्यार्थियों के आवेदन लंबित; फीस के लिए कालेज बना रहे दबाव, अब विभाग ने सत्यापन में देरी पर संस्थानों को जिम्मेदार ठहराया

भोपाल, (एजेंसी)। छात्रवृत्ति विद्यार्थियों की पढ़ाई का सहारा है, लेकिन मध्य प्रदेश में यही सहारा चार शैक्षणिक सत्र से सरकारी प्रक्रिया में अटका हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले करीब १८० कॉलेजों के लगभग ३० हजार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। २०२२-२३ से २०२५-२६ तक के आवेदन लंबित हैं। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से विद्यार्थियों पर कॉलेज फीस जमा करनेका दबाव बढ़ रहा है।

मामला सामने आने के बाद अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने सभी लंबित आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने साफ किया है कि पात्र विद्यार्थियों के आवेदन का सत्यापन समय पर नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्थान जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों ने अलग-अलग शैक्षणिक सत्रों में आवेदन किए थे। इनमें २०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५ और २०२५-२६ के आवेदन शामिल हैं। आवेदन के बाद संस्थान स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन होना है। इसके बाद विभागीय स्तर की प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि मिलती है। लेकिन बड़ी संख्या में आवेदन सत्यापन के स्तर पर ही लंबित रह गए। इसका सीधा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ा, जो छात्रवृत्ति की राशि के भरोसे अपनी फीस और पढ़ाई से जुड़े खर्च पूरे करते हैं।

फीस जमा नहीं की तो कॉलेजों का दबाव

छात्रवृत्ति में देरी का असर केवल बैंक खाते तक सीमित नहीं है। कई विद्यार्थियों के सामने कॉलेज की फीस जमा करने की समस्या खड़ी हो गई है। छात्रवृत्ति आने की उम्मीद में फीस का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों पर अब संस्थानों की ओर से भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई जारी रखना चुनौती बन रहा है। एक तरफ आवेदन स्वीकृत होने और राशि मिलने का इंतजार है, दूसरी तरफ कॉलेज फीस की मांग कर रहे हैं।

पोर्टल की तकनीकी खामी बनी बड़ी अड़चन

संस्थानों की ओर से विभाग को बताया गया है कि कई आवेदनों के सत्यापन में पोर्टल की तकनीकी समस्याएं बाधा बन रही हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आने के कारण संस्थान आवेदन आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। विभाग ने अब संस्थानों से कहा है कि पोर्टल पर तकनीकी समस्या आने पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर तत्काल विभाग को भेजा जाए, ताकि समस्या का निराकरण कराया जा सके। विभाग का उद्देश्य यह है कि तकनीकी खामी के कारण पात्र विद्यार्थियों के आवेदन और लंबित न रहें तथा उन्हें केन्द्रांश का भुगतान समय पर हो सके।

अब जिम्मेदारी तय करने की तैयारी

इस मामले में विभाग ने केवल आवेदन निपटाने के निर्देश नहीं दिए हैं, बल्कि सत्यापन में देरी की जिम्मेदारी भी तय करने के संकेत दिए हैं। विभाग का कहना है कि सभी पात्र विद्यार्थियों के आवेदन का जल्द सत्यापन किया जाए। देरी के कारण छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब होता है तो संबंधित संस्थान जिम्मेदार होंगे। यानी अब तकनीकी समस्या के नाम पर लंबे समय तक आवेदन लंबित रखने की गुंजाइश कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि असली परीक्षा यह होगी कि चार सत्र से अटके आवेदन कितनी तेजी से निपटते हैं और विद्यार्थियोंके खातोंमें छात्रवृत्तिकी राशि कब तक पहुंचती है।

सवाल सिर्फ पोर्टल का नहीं, समय पर भुगतान का भी

छात्रवृत्ति की ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है, लेकिन जब आवेदन महीनों या वर्षों तक सत्यापन के स्तर पर अटके रहें तो पूरी व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल उठता है। तकनीकी समस्या यदि वास्तविक है तो उसका समाधान विभाग और पोर्टल व्यवस्था को करना है; उसका वित्तीय बोझ विद्यार्थियों पर नहीं पडऩा चाहिए। अब विभाग के आदेश के बाद नजर इस बात पर है कि २०२२-२३ से लंबित आवेदनों का निपटारा कब तक होता है और करीब ३० हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि कब मिलती है।

बागेश्वर धाम से १७० लोगों के लापता होने का मामला

७५ दस्तयाब, अभी भी ९५ लोगों का नहीं मिला सुराग

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर धाम से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हाल ही में प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जुड़े विवादों के बीच, बागेश्वर धाम से पिछले कुछ समय में १७० लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। इस आंकड़े में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगस्त और सितंबर के महीनों में ७५ लोगों को ढूंढ निकाला है, लेकिन अभी भी ९५ लोगों का कोई सुराग नहीं लग सका है, जिससे उनके परिजन खासे परेशान हैं और अपनोंकी तलाशकी गुहार लगा रहे हैं।

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा का कहना है कि बागेश्वर धाम में देश-विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और कई बार लोग भीड़भाड़ में अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं या बिना बताए कहीं चले जाते हैं। विभिन्न राज्यों से दस्तयाब: पुलिस टीमों ने तकनीकी मदद और छानबीन करते हुए बिहार, झारखंड, गुजरात सहित कई अन्य राज्यों में दबिश दी और अब तक ७५ लोगों को सुरक्षित दस्तयाब कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

सूचना न देने की बात

पुलिस के मुताबिक, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी, जिससे गुमशुदगी का आंकड़ा भ्रमित कर रहा था। एसपी के अनुसार, शेष बचे ९५ लापता लोगों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार जुटी हुई हैं।

धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद बढ़ी चिंता

यह बड़ा आंकड़ा ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खुद धाम आने वाली माताओं-बहनों से अपील की थी कि वे अकेली आने से बचें और अनजान लोगों या सेवादारों पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। उन्होंने स्पष्ट किया था कि धाम का क्षेत्र लगभग ५ किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने बड़े क्षेत्र में हर व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं है। इसलिए भक्तों को दर्शन करने के बाद सुरक्षित अपने घर लौट जाना चाहिए। बहरहाल, इस खुलासे के बाद से जहां एक तरफ पुलिस बाकी ९५ गुमशुदा लोगों को तलाशने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर लोगों के लापता होने का यह मामला चिंता का विषय बना हुआ है।

मंत्री के घर के बाहर भूख हड़ताल का ऐलान करना भाजपा विधायक को पड़ा भारी

कालू सिंह ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष ने थमाया नोटिस, ३ दिन में मांगा जवाब

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हडक़ंप मच गया जब धार जिले के धरमपुरी से बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर ने अपनी ही पार्टी की केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के निवास के बाहर भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया था। इस मामले में अब पार्टी संगठन ने कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और तीन दिन के भीतर जवाब तलब किया है। धरमपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर ने धामनोद नगर पालिका के सीएमओ पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने और सुनवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया था। इसी के विरोध में विधायक ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के धार स्थित सरकारी आवास के बाहर ही भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया था। अपनी ही सरकार और केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर विधायक के इस तीखे तेवर से जिले की सियासत में भूचाल आ गया था और यह मुद्दा विपक्षी दलोंके बीच भी चर्चाका विषय बन गया था।

प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया नोटिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने अनुशासनहीनता मानते हुए तुरंत कार्रवाई की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से ५ अक्टूबर को जारी पत्र में विधायक को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है। विगत दिनों आपके द्वारा जो आचरण किया गया, वह अत्यंत आपत्तिजनक है। आपके द्वारा किया गया आचरण पार्टी अनुशासन के अनुरूप नहीं है। अत: ३ दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण देवें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची प्रतिलिपि

अनुशासनहीनता के इस मामले को पार्टी ने बेहद उच्च स्तर पर संज्ञान में लिया है। जारी किए गए इस कारण बताओ नोटिस की प्रतियां राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब सहित पार्टी संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से भेज दी गई हैं। अब देखना यह होगा कि विधायक कालू सिंह ठाकुर तीन दिन के भीतर अपने स्पष्टीकरण में क्या सफाई देते हैं और पार्टी का अगला कदम क्या होता है।

करंट लगने से आंख-कान खराब होने और ७१ हजार मजदूरी रोकने का आरोप

परिवार संग कलेक्ट्रेट पहुंचा इलेक्ट्रानिक मिस्त्री

गुना, (एजेंसी)। शहर के गोपालपुरा कैंट क्षेत्र निवासी एक इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री ने हाट रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक पर करीब ७१ हजार ८१० रुपए मजदूरी नहीं देने और काम के दौरान लापरवाही के कारण करंट लगने का आरोप लगाया है। मंगलवार को पीड़ित अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा और आवेदन देकर बकाया राशि दिलाने, उपचार कराने तथा मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की।

पीड़ित शिवराज नामदेव ने आवेदन में बताया कि वह अगस्त २०२१ से हाट रोड स्थित संजय इलेक्ट्रॉनिक पर रिपेयरिंग का काम करता था। आरोप है कि दुकान संचालक संजय जैन उसे शुरुआत में ७,५०० रुपए और बाद में ८ हजार रुपए प्रतिमाह वेतन देता था। शिवराज के अनुसार उसने मकान कर तथा अन्य जरूरतों के लिए वेतन का कुछ हिस्सा दुकान संचालक के पास ही जमा रहने दिया था। वर्ष २०२२ से मार्च २०२५ तक की गणना के अनुसार उसकी कुल बकाया मजदूरी १ लाख ४ हजार ८१० रुपए बनी थी, जिसमें से अलग-अलग समय पर ३३ हजार रुपए मिलने के बाद ७१ हजार ८१० रुपए अभी बाकी होने का दावा किया गया है।

आवेदन में शिवराज ने आरोप लगाया कि १० मार्च २०२५ को दुकान पर टेलीविजन की मरम्मत करते समय बिजली प्रवाहित रिसीवर उठाने से उसे तेज करंट लगा और वह जमीन पर गिर गया। उसका दावा है कि इसके बाद दोनों कानों में संक्रमण और आंखों में गंभीर परेशानी हुई। दुकान संचालक ने इलाज कराने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में २५ मार्च को उसे काम से हटा दिया गया।

पीड़ित ने यह भी दावा किया कि जनवरी २०२६ में दुकान संचालक उसके घर आया और २० हजार रुपए देने, इलाज कराने तथा दोबारा काम पर रखने की बात कही, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास है। अब परिवार ने प्रशासन से मजदूरी दिलाने, उपचार सहायता और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

महापुरुषों को नमन कर स्वच्छता का लिया संकल्प

जबलपुर, (एजेंसी)। देश की आजादी में अपना महान योगदान देने वाले महापुरुषों, राष्ट्रनायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करना हम सभी के लिए गौरव का अवसर है। इसी भावना के साथ सांई विजन एनजीओ जबलपुर द्वारा पिसनहारी मढ़िया चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।

इस अवसर पर समाजसेवी सुमन कुमार जैन ने कहा कि संस्कारधानी जबलपुर को गौरवान्वित करने में स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके त्याग और संघर्ष से हमें राष्ट्रभक्ति, देशप्रेम और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की प्रेरणा मिलती है।

धान, ज्वार और बाजरा बेचनेको तीन लाखसे अधिक किसानों ने कराया पंजीयन

समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए १० अक्तूबर तक पंजीयन का मौका, ११०० केंद्रों पर चल रही प्रक्रिया

भोपाल, (एजेंसी)। खरीफ विपणन वर्ष २०२६-२७ में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए मध्य प्रदेश में अब तक तीन लाख से अधिक किसान पंजीयन करा चुके हैं। किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया १० अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसके लिए प्रदेशभर में ११०० पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक पंजीयन जबलपुर संभाग में १ लाख ४७ हजार ८२४ किसानों ने कराया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से निर्धारित समय सीमा में पंजीयन कराने की अपील की है।

शराब के लिये रुपये नहीं देने पर मारपीट

जबलपुर, (एजेंसी)। हनुमानताल थाना अतंर्गत करिया पाथर स्कूल के पीछे दुर्गा मंदिर के पास शराब पीने के लिए रुपए नहीं मिलने की बात पर एक बदमाश ने एक युवक पर चाकू व डंडे से हमला कर घायल कर दिया। हनुमानताल पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार करिया पाथर स्कूल के पास जानकीदास मंदिर के पीछे हनुमानताल निवासी ३८ वर्षीय जितेंद्र कुमार गत दोपहर २ बजे काम से वापस अपने घर जा रहा था, तभी घायल कर दिया।

किसानों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों और विपणन संस्थाओं में पंजीयन की सुविधा निश्शुल्क उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा किसान एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते हैं। इन केंद्रोंपर अधिकतम ५० रुपये शुल्क निर्धारित है।

इन किसानों का पंजीयन सिर्फ सहकारी केंद्रों पर

सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों के लिए पंजीयन की व्यवस्था अलग रखी गई है। इन किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समितियों के केंद्रों पर किया जाएगा। पंजीयन के दौरान आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा।

सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना पंजीयन पूरा करा लें, ताकि खरीफ फसलोंको समर्थन मूल्यपर बेचनेमें किसी तरहकी परेशानी न हो।

फतेहगढ़ समिति के राशन दुकान विक्रेताओं का २४९ महीनों का वेतन लंबित

कलेक्टरेट पहुंचे सेल्समैनों ने कलेक्टर से लगाई गुहार, विभाग बोला-पहले वारदाने के पैसे जमा कराओ

गुना, (एजेंसी)। प्राथमिक लघु वनोपज समिति फतेहगढ़ के अंतर्गत संचालित चार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं का लंबे समय से वेतन लंबित होने के कारण उनके सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मंगलवार को पीडित सेल्समैनों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा। सेल्समैनों ने २४९ विक्रेता-माह का बकाया मानदेय दिलाने, समिति के बैंक खातों की जांच कराने और सहकारिता विभाग द्वारा पूर्व में की गई कार्रवाई की पारदर्शी जानकारी देने की मांग की है। इधर विभाग ने उल्टे राशन विक्रेताओं पर वारदाने के पैसे जमा नहीं करनेकी बात कही। जो लगभग ६ लाख रुपएसे अधिक है।

कलेक्टोरेट पहुंचे पीडितों ने बताया कि फतेहगढ़ समिति के तहत संचालित राशन दुकानों के विक्रेताओं का वर्षों से मानदेय नहीं मिला है। दुकानवार विवरण के अनुसार रामनगर दुकान के विक्रेता अरविंद किरार का ९६ माह, अजरोडा के विक्रेता अनिल मीना का १८ माह, डिगडोली के विक्रेता दीनदयाल भील का २० माह और कर्राखेड़ा के विक्रेता रूपेश शर्मा का सर्वाधिक ११५ माह का मानदेय अटका हुआ है। इस प्रकार कुल २४९ महीनों का वेतन लंबित है, जिससे विक्रेताओं और उनके परिवारों का जीवन-यापन दुभर हो गया है। आवेदकों ने कलेक्टर से मांग की है कि समिति के सभी बैंक खातों, कैशबुक, लेजर, भुगतान रजिस्टर और जमा बारदाना राशि का मिलान किसी निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी से कराया जाए। साथ ही यह स्पष्ट किया जाए कि इतने लंबे समय तक मानदेय रुकने का वास्तविक कारण क्या है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। विक्रेताओं ने पूर्व में दिए गए आवेदनों पर हुई कार्रवाई की बिंदुवार जानकारी देने और समय-सीमा तय कर बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान कराने की गुहार लगाई है।

इनका कहना है

इन्होंने सिर्फ अपना पक्ष रखा है। इन राशन दुकानदारों ने वारदाने का पैसा अभी तक जमा नहीं किया है। इस संबंध में हम मौके पर इन्हें लेटर भी दे रहे थे लेकिन इन्होंने लेटर नहीं लिया। करीब ६ लाख रुपए से अधिक का वारदाने का भुगतान लंबित है। या तो यह वारदाने के पैसे जमा करा दें या वेतनमें एडजस्ट करा लें।-दिनेश चौरसिया, उपायुक्त सहकारिता विभाग गुना

भोपाल में ४७ भैंसें बनीं नगर निगम की मुसीबत

१० महीने में चारे पर खर्च हुए १६ लाख, कोर्ट केस से अटकी नीलामी

भोपाल, (एजेंसी)। भोपाल नगर निगम के लिए ४७ भैंसें अब बड़ा खर्च और परेशानी का कारण बन गई हैं। अरवलिया स्थित नगर निगम के कांजी हाउस में रखी इन भैंसों के चारे पर पिछले करीब १० महीने में १६ लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। मामला अदालत में लंबित होने के कारण निगम इनकी नीलामी भी नहीं कर पा रहा है। अब निगम इन भैंसों को वापस इटखेड़ी पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम के गोवर्धन प्रोजेक्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मांगी है। इसके बाद इटखेड़ी पुलिस को पत्र भेजकर भैंसें वापस लेने का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही अब तक इनके चारे और देखभाल पर हुए खर्च की पूरी जानकारी भी पुलिस को दी जाएगी।

जनवरी से कांजी हाउस में हैं भैंसें

नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, इटखेड़ी पुलिस ने जनवरी २०२६ से अब तक ४९ भैंसों को अवैध तरीके से ट्रकों में ले जाते हुए पकड़ा था। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए ट्रक और भैंसों को जब्त किया था। मामला कोर्ट में पेश होने के बाद ट्रक तो छोड़ दिया गया, लेकिन भैंसें नगर निगम के कांजी हाउस में ही रखी रहीं। मामला अदालत में लंबित होने के कारण इनकी देखभाल और चारे की जिम्मेदारी नगर निगम पर आ गई। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, इस दौरान भैंसों के चारे पर १६ लाख रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं।

९ भैंसों की मौत, ४ बछड़े भी हुए

कांजी हाउस में रखी ४९ भैंसों में से अब तक ९ की मौत हो चुकी है, जबकि इस दौरान ४ बछड़ों का जन्म भी हुआ। किसी भैंस की मौत होने पर गोवर्धन प्रोजेक्ट को इटखेड़ी पुलिस को सूचना देनी पड़ती है। पुलिस की अनुमति के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होती है। अधिकारियों के मुताबिक, हाल ही में करीब ४५ दिनों के भीतर चार भैंसों की मौत हुई। इससे कांजी हाउस में इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को लंबे समय तक रखने और उनकी देखभाल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

नीलामी की कोशिश भी नहीं हो सकी

नगर निगम ने पहले इन भैंसों की नीलामी के जरिए उनके रखरखाव पर हुए खर्च की भरपाई करने का प्रयास किया था। इसके लिए इटखेड़ी पुलिस से दो बार अनुमति मांगी गई, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देकर अनुमति नहीं दी गई। अब निगम के सामने भैंसों को लंबे समय तक रखने और लगातार बढ़ रहे चारे के खर्च की चुनौती है। ऐसे में गोवर्धन प्रोजेक्ट अब पुलिस को भैंसें वापस सौंपने की तैयारी कर रहा है। साथ ही अब तक हुए पूरे खर्च का ब्योरा भी पुलिस को दिया जाएगा।

धूल के गुबार और गड्ढों के बीच सफर, जिम्मेदारों की चुप्पी पर सवाल

बुरहानपुर (ईएमएस)। सिंधी बस्ती चौराहा से कलेक्टर चौराहे तक सड़क बदहाल धूल के गुबार में सांस लेना मुश्किल, गड्ढों में हिचकोले खा रहे वाहन लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग फिर भी जिम्मेदार अफसर और नेता बेपरवाह सिंधी बस्ती चौराहे से कलेक्टर चौराहे तक का मार्ग इन दिनों सड़क कम और धूल-गड्ढों का रास्ता ज्यादा नजर आ रहा है। सड़क पर जगहजगह बने गहरे गड्ढे और उड़ती धूल वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। जिम्मेदार है कि इस धूल को पानी का छिड़काव कर दबाने के प्रयास में लगे दिनभर इस मार्ग से गुजरने वाले सैकड़ो दोपहिया वाहन चालक धूल के गुबार के बीच आंखों में मिर्चजैसी जलन सहते हुए सफर करने को मजबूर हैं। वहीं गड्ढों के कारण वाहनों को हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग की बद हाली कोई नई समस्या नहीं है। लंबे समय से सड़क के निर्माण और सुधार की मांग उठाई जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से अब तक ठोस पहल दिखाई नहीं दी।

कागजों पर ४५ डाक्टर, जमीन पर सिर्फ १५

आयुष्मान भारत योजना में भुगतान के लिए स्टाफ की संख्या का खेल, एक डाक्टर-नर्स के नाम चार-चार बार दर्ज, सभी ४५ प्रविष्टियों में संचालक का मोबाइल नंबर; फर्जी पैथोलाजी रिपोर्ट का भी आरोप

भोपाल, (एजेंसी)। आयुष्मान भारत योजना में मरीजों के इलाज के नाम पर अस्पतालों में स्टाफ और सुविधाओं की उपलब्धता का सत्यापन कितना अहम है, इसका एक मामला राजधानी में सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की जांच में करोंद स्थित सृष्टि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में दर्ज डॉक्टरों और वास्तविक उपलब्ध स्टाफ की संख्या में बड़ा अंतर सामने आया। जांच एजेंसी के अनुसार अस्पताल ने आयुष्मान पोर्टल पर ४५ डॉक्टर और स्टाफ की प्रविष्टियां दर्ज की थीं, जबकि मौके पर करीब १५ डॉक्टर ही उपलब्ध पाए गए। ईओडब्ल्यू ने अस्पताल संचालक राजकुमार सूर्यवंशी और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं ३१८(४), ३३६(३), ३४०(२) और ६१(२) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। एजेंसी अब यह जांच कर रही है कि आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल को कितनी राशि का भुगतान हुआ और उसमें से कितनी राशि नियमों के विपरीत प्राप्त की गई।

संख्या बढ़ाने के लिए नाम दोहराए

जांच में सामने आया कि पोर्टल पर दर्ज ४५ प्रविष्टियों में कई डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के नाम एक से अधिक बार दर्ज किए गए थे। आरोप है कि कुछ नामों को चार-चार बार दोहराकर अस्पताल में आवश्यक स्टाफ की संख्या पूरी दिखाई गई। खास बात यह रही कि इन ४५ प्रविष्टियों में दर्ज मोबाइल नंबर अस्पताल संचालक का ही बताया गया है। इससे जांच एजेंसी के सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या आयुष्मान योजना के लिए निर्धारित मानव संसाधन संबंधी शर्तों को पूरा दिखाने के लिए कागजों पर अतिरिक्त स्टाफ खड़ा किया गया था।

७०९ मरीजों का रिकार्ड, लेकिन दस्तावेज नहीं

आयुष्मान के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष २०२५ में अस्पताल में ७०९ मरीजों के इलाज दर्ज हैं। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने अस्पताल प्रबंधन से डॉक्टरों के नियुक्ति-पत्र, वेतन भुगतान, उपस्थिति रजिस्टर, पैथ